भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3138

उत्तर देने की तारीखः 22.0**3**.201**8**

अल्‍पसंख्‍यकों के लिए विश्‍वविद्यालय

3138. डा॰ प्रदीप कुमार बालमुचूः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार देश भर में जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अधिक है, वहां**

**अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की योजना बना रही है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए समिति गठित की गई है; और**

**(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इस संबंध में समिति ने**

**क्या-क्या सिफारिशें की हैं**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (घ): अल्‍पसंख्‍यकों के लिए विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्‍वायत्‍त संस्‍था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) ने अल्‍पसंख्‍यकों के शैक्षिक विकास को सुकर बनाने की दृष्‍टि से देश के विभिन्‍न भागों में संस्‍थाओं की स्‍थापना के लिए तौर-तरीकों की जांच करने के लिए एक 11 सदस्‍यीय समिति का गठन किया है।

उपर्युक्‍त समिति ने अपनी रिपोर्ट एमएईएफ को 06.07.2017 को प्रस्‍तुत कर दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अल्‍पसंख्‍यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं के तीन स्‍तरीय मॉडल की सिफारिश की है जो इस प्रकार है:

* नीचे के स्‍तर पर 211 केन्‍द्रीय स्‍कूल;
* मध्‍य स्‍तर पर 25 सामुदायिक कालेज; और
* शीर्ष स्‍तर पर 5 राष्‍ट्रीय संस्‍थान

\*\*\*\*\*